



प्राकृतिक संसाधन संरक्षण तथा संघृत विकास के विशेष संदर्भ में : एक विवेचनात्मक अध्ययन

□ डॉ० विनीत नारायण दूबे

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में 'संघृत' विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों तथा पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं तो उनके उपयोग में सदैव सावधानी बरतते हैं। नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में अनवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग में विशेष ध्यान अपेक्षित रहता है। नवीकरणीय संसाधनों की प्राप्यता तो भविष्य में बनी रहने की सम्भावना होती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग के बाद सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं तथा निकट भविष्य में उनका निर्माण भी जल्दी संभव नहीं होता है। संघृत विकास, विकास की एक ऐसी अवधारणा है, जो वर्तमान में किसी भी संसाधन के प्रयोग के लिए प्रतिबन्ध नहीं लगाती है, बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोग करने के लिए अवशेष के रूप में संरक्षण प्रदान करने की बात करती है।

धरातल का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और पृथ्वी की जलवायुविक दशाओं में नकारात्मक परिवर्तन प्रारम्भ हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन एक गम्भीर समस्या के रूप हमारे सामने है, जिससे निपटना मानव सभ्यता के लिए अनिवार्य होता जा रहा है, आज राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह विचार-विमर्श का प्रमुख विषय बन चुका है। सभी परिचर्चाओं का यही प्रश्न है कि किन उपायों द्वारा पृथ्वी पर हो रहे जलवायु परिवर्तनों से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा जा सके? पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों पर भी नियंत्रण करने की बातें की जा रही हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन तथा सतत तापमान वृद्धि के कारणों पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली प्रमुख परिचर्चाओं तथा सम्मेलनों में, ब्राजील में आयोजित 'रियो पृथ्वी सम्मेलन-1992, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर सहमति बनी तथा 'यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) नाम दिया गया। वातावरण में बढ़ रही ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर रोकथाम करना इस संधि का प्रमुख उद्देश्य था। 'क्योटो सम्मेलन'-1997, बाली सम्मेलन-2007, कोपेन हेगन सम्मेलन, कोप - 15 तथा दिसम्बर, 2010 में मेक्सिको के शहर 'कानकुन' में हो रहे, 192 सदस्य देशों की उपस्थिति में आयोजित जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित सम्मेलन कोप -16 मैक्सिको, 2010, कोप-17,

डरबन (दक्षिण अफ्रीका) 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर, 2011, तथा कोप-18/ब्डच8 दोहा (कतर) 26 नवम्बर से 8 दिसम्बर, 2012, कोप -19, वारसा पोलैण्ड, नवम्बर-2013, कोप-20 पीरू, लीमा 1-12 नवम्बर 2014, कोप -21 सी.एम.पी.-11, फ्रांस, पेरिस 30 नवम्बर-11 दिसम्बर, 2015 कोप-22 मर्राकेक्ष, मोरक्को, 7-18 नवम्बर 2016, सीएमपी-12 कोप-23, सीएमपी-13, बॉन, जर्मनी 06-17 नवम्बर 2017 में आयोजित तथा कोप-24 सीएमपी-14 काटोवाइस, पोलैण्ड में, नवम्बर 2018 में प्रस्तावित है, आदि प्रमुख हैं। इन सम्मेलन में यदि निष्पक्षता पूर्वक विकसित, विकासशील तथा पिछड़े हुए देशों के मध्य एक समझौता किया जाय तथा सभी देश उसका अनुपालन करें। हम इस भूमंडलीय समस्या का समाधान पा सकते हैं। धरती को बचाना हम सभी की अब मजबूरी बन चुकी है। ग्रीष्म ऋतु और गर्म होती जा रही है, शीतकाल का अंतराल घट रहा है, बिना मौसम वर्षा, प्राकृतिक आपदाओं का घटित होना, जैव विविधता में दिनानुदित हो रहे परिवर्तन, विभिन्न जीव तथा वनस्पति प्रजातियों का समाप्त होना, कौवे, गिद्ध, चील तथा गौरों का विलुप्त होना, शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा ध्वनि, वायु तथा जल प्रदूषण, गहराता जल संकट, बढ़ता सागरीय जल स्तर घटता भू-जल स्तर तथा ग्रीष्म काल में पेयजल की गम्भीर समस्याएँ, असाध्य रोगों का प्रसार आदि वैश्विक

जलवायु परिवर्तन तथा सतत तापमान वृद्धि के ही दुष्परिणाम नहीं तो और क्या है? 'वर्ल्ड इकोनॉमिक आउट लुक' जनवरी-2010 के आंकड़ों के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जक देशों में क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्रिटेन (यू0के0) कोरिया आदि प्रमुख हैं। सम्पूर्ण विश्व स्तर पर कुल-28953 लाख टन, कार्बन डाइआक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति सार्वजनिक उत्सर्जन, कनाडा द्वारा-60 तथा स0रा0अ0 द्वारा-20.6 लाख टन उत्सर्जन किया जा रहा है, भारत की हिस्सेदारी प्रति व्यक्ति 1.2, रूस द्वारा, 12.6, जापान द्वारा 9.9 जर्मनी-9.8, ब्रिटेन-9.8, कोरिया-9.7 तथा विश्व औसत 4.5 लाख टन औसत प्रति व्यक्ति है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में क्रमशः हिस्सेदारी वाले देशों में सर्वोच्च शिखर पर चीन 20.09 प्रतिशत, अमेरिका 17.89 प्रतिशत, रूस 07.53 प्रतिशत, भारत 04.10, जापान 03.79, जर्मनी 02.56, ब्राजील 02.48, कनाडा 01.95, ब्रिटेन 01.55 तथा इंडोनेशिया 01.49 प्रतिशत का हिस्सेदार देश है।

प्रस्तुत शोध-पत्र में वैश्विक जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारणों, प्रभावों तथा नियंत्रणकारी उपायों का अध्ययन भारत के विशेष संदर्भ में किया गया है। वर्ष 1800 ई0 से अब तक जहाँ पृथ्वी का तापमान, 0.740 से0 की वृद्धि हुई वहीं, 2100 ई0 तक 1.80-40 से0 वृद्धि का अनुमान है। ध्रुवों पर 200 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी। बीसवीं शताब्दी में समुद्र तल में जहाँ 10-20 सेमी0 जल तल वृद्धि हुई है, वही 2100 ई0 तक 18-59 सेमी0 वृद्धि का अनुमान है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रमुख नियंत्रणकारी उपायों में कार्बन उत्सर्जन में नियंत्रण, जल संरक्षण, वाहनों का उचित प्रयोग, विभिन्न वस्तुओं का रिसाइकिल प्रयोग, बायो ईंधन प्रयोग, वायु सौर, ज्वारीय तथा भू-तापीय उर्जा के प्रयोग का विस्तार, ग्रीन हाउस गैसों का सीमित प्रयोग आदि किये जा सकते हैं। भारतीय संदर्भ में भी समुद्र जल स्तर में वृद्धि से महाराष्ट्र, तमिलनाडू आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों के जलमग्न

होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी मानकर पर्यावरण की रक्षा तथा पृथ्वी को बचाने का संकल्प नहीं लेगा तक हम पृथ्वी की रक्षा नहीं कर सकेंगे। विश्व स्तरीय वायुमंडल में पायी जाने वाली 1 प्रतिशत गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन उत्सर्जक गैसों में क्रमशः कार्बनडाईआक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन ओजोन, मीथेन, क्लोरोफोरोकार्बन तथा अन्य डाइड्रोकार्बन्स का अतिआवश्यक होने पर अल्प मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रस्तावना- पर्यावरण तथा संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में संघृत विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों तथा पर्यावरण के संरक्षण की बात करते हैं तो उनके उपभोग में सदैव सावधानी बरतते हैं। नवीकरणीय संसाधनों की तुलना में अनवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग में विशेष ध्यान अपेक्षित रहता है। नवीकरणीय संसाधनों की प्राप्यता तो भविष्य में बनी रहने की सम्भावना होती है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग के बाद सदा-सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं तथा निकट भविष्य में उनका निर्माण भी जल्दी संभव नहीं होता है। संपोषी, संघृत विकास विकास की एक ऐसी अवधारणा है, जो वर्तमान में किसी भी संसाधन के प्रयोग के लिए प्रतिबन्ध न ही लगाती, बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी उपयोग करने के लिए अवशेष के रूप में संरक्षण प्रदान करने की बात करती है। पहले प्रकृति तथा मानव का सम्बन्ध मित्रवत् था, हम किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपभोग बिना प्रकृति को क्षति पहुँचाते हुए सीमित रूप से करते थे। मनुष्य ने धीरे-धीरे अपनी सुख-सुविधाओं, उद्योग के विकास तथा कृषि में आयी 'हरित क्रान्ति' के बाद तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन बिना प्रकृति का ध्यान दिये हुए करना प्रारम्भ किया। उद्योग-धन्धों, सड़कों, रेल मार्गों, अधिवासों तथा कृषि भूमि के विस्तार के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे वनों का विनाश हुआ। जहाँ वनों का विस्तार पचास प्रतिशत से भी अधिक भू-भाग पर था वह धीरे-धीरे प्रकृति के लिए आदर्श 33 प्रतिशत

भी नहीं रहा जो एक चिन्तनीय विषय है। सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन के परिणाम, विनाश के रूप में सामने आया, कमी अतिवृष्टि, कमी अनावृष्टि, हिमपात, वैश्विक तापन, बादल फटना, वनाग्नि का प्रकोप, भू-स्खलन, हिमस्खलन, जैव विविधता का नष्ट होना, विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव जन्तुओं की प्रजातियों का समाप्त होना तथा विभिन्न लाइलाज बीमारियों का प्रकोप आदि। विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं को देखते हुए हमने निर्णय किया कि अब प्रकृति के साथ मित्रवत् सम्बन्ध बनाये रखने की ही आवश्यकता है। 'सतत् विकास' की अवधारणा का मूल विचार प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अन्तर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रायोजित 'विश्व संरक्षण रणनीति, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा प्रकृति (पृथ्वी) को बचाने के लिए विश्वव्यापी कोष आदि संगठनों द्वारा दिया गया विचार है। कोई भी समाज तब तक आत्मनिर्भर व सतत् विकास को नहीं बनाये रख सकता है, जब तक कि उसकी जीवनदायिनी व्यवस्था तथा जैव विविधता को संरक्षण न प्रदान किया जाय। प्रकृति के हम जितने ही निकट होंगे वह उतना ही अधिक हमारे कल्याण के लिए कार्य करती है। पुनर्नवीनीकरण अयोग्य संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जाय। पारिस्थितिकी तंत्र में इन संसाधनों की वहन क्षमता को ध्यान में रखकर ही उनका उपयोग किया जाना चाहिए। वर्ष 1992 में आयोजित 'रियो' पृथ्वी सम्मेलन (ब्राजील) में सम्पन्न 'विश्व पर्यावरण तथा विकास सम्मेलन' की पृष्ठभूमि में 'सतत् विकास के यही विचार आधार बने। 'सतत् विकास' का प्रमुख विचार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व सतत् उपयोग करते हुए दीर्घकाल तक आर्थिक विकास तथा उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करना है तथा न्यायपूर्वक प्रकृति के साथ मित्रवत् रहकर जीवन व्यतीत करना है। Our Common Future 'हमारा साझा भविष्य' के विचारानुसार "ऐसी विकास की नीति जो हमारे वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बिना समझौता किये अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं को सुरक्षित रखें। सतत् विकास एक अविच्छिन्न विकास से सम्बन्धित है, जिसमें हम अपने जीवन स्तर में सुधार करते हुए अपनी समस्त सम्पदा

व धरोहर को अक्षुण्ण रूप से अगली पीढ़ी तक पहुँचा सकें। 'संघृत विकास संविकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्य रूप से संविकास ऐसा विकास है जो सामाजिक दृष्टि से वांछित हो, आर्थिक दृष्टि से वहनीय हो एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से संपुष्ट भी हो। "Ecodevelopment is a kind of development that is socially desirable, economically viable and ecologically sound" संघृत विकास के अन्य समानार्थी प्रयुक्त शब्दों में संपोषी विकास, पोषणीय विकास, वहनीय या टिकाऊ विकास, जीवन धारणीय विकास, सदाबहार एवं दीर्घकालीन विकास प्रमुख है।

अध्ययन उद्देश्य- प्रस्तुत शोध-पत्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि 'संघृत विकास' द्वारा किस प्रकार अपने पर्यावरण तथा संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे पृथ्वी का पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त रहे। हमारी पृथ्वी के समाप्तप्राय (अनवीकरणीय) संसाधन भी हमारे प्रयोग में आते रहे तथा भावी पीढ़ी के लिए भी अवशेष रहे। संसाधनों के संघृतता को बनाये रखने के उपायों पर भी विचार किया गया है।

ऑकड़े व विधि तंत्र : प्रस्तुत शोध-पत्र में द्वितीयक ऑकड़ों पर आधारित निष्कर्षों का प्रयोग किया गया है तथा विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलनों के विचार भी रखे गये हैं।

संघृत विकास 'विकास' में भूमिका : विकास को अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण तक सीमित रखने का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि आर्थिक प्रगति की सामाजिक लागत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी आर्थिक कार्य की लागत उसके लाभों एवं गणना में उन तत्वों को सम्मिलित ही नहीं किया जाता था जो सीधे आर्थिक क्रियाकलापों से सम्बन्धित न हो। किसी उद्योग धन्धे के आर्थिक क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण कितना दुष्प्रभावित होता है, इसका उत्तरदायित्व उद्योगपतियों का नहीं माना जाता था। औद्योगिक प्रदेशों में गहराते पर्यावरण अवक्रमण ने जनजीवन को काफी दुष्प्रभावित किया। जब मिडोज प्रमृति की पुस्तक 'The Limits of Growth' 1997 में प्रकाशित हुई। इन्हीं समस्याओं पर विचार के लिए स्टाकहोम शिखर

सम्मेलन-1972, जिसमें 1987 में ब्रुन्टलैण्ड आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया तथा कहा कि "पर्यावरण की अवहेलना तथा उपेक्षा करके 'संघृत विकास' नहीं किया जा सकता है। विश्व के 'पर्यावरण मित्र' देशों की सूची में 163 देशों में आइसलैण्ड प्रथम स्थान पर, जबकि जापान 20वें, अमेरिका 61वें, चीन 121वें तथा भारत 123वें स्थान पर पर्यावरण का मित्र देश है, अर्थात् आइसलैण्ड, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान की तुलना में हमसे पर्यावरण की कम घनिष्ठ मित्रता है।

विकास की परिभाषा को व्यापकता प्रदान करते हुए इसमें अन्तर्पीढ़ी साम्य' को भी जोड़ा गया। विकास का उद्देश्य बिना भावी पीढ़ी को अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अवसर से वंचित किये, विद्यमान पीढ़ी की मौलिक आवश्यकताओं की संपूर्ति है। "Fulfilment of the basic needs of the present generation without compromising the opportunity of the future generations to fulfill their own needs." रियो पृथ्वी सम्मेलन-1992 में मानव विकास को संघृत विकास का केन्द्र मानकर प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई। रियो का 1992 को सम्मेलन का एजेंडा-21 इन्हीं से सम्बन्धित है। बाद में आयोजित किये गये अन्य सम्मेलनों जोहानेसवर्ग सम्मेलन-2002, वाली सम्मेलन (इण्डोनेशिया)-2007 कोप-15, कोपेनहेगन, दिसम्बर, 2009 तथा कानकुन, मैक्सिको (कोप-16) 2010 आदि इन्हीं से सम्बन्धित सम्मेलन हैं, जिनकी पर्यावरण के बचाव में यह महत्वपूर्ण भूमिका है। वहनीय (टिकाऊ) विकास पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से सामान्य मुहावरा बन गया है। यह विकास का ऐसा प्रारूप है, जो पृथ्वी पर मानव की विद्यमान एवं भावी पीढ़ी को कम से कम मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति दीर्घकाल तक करने में समर्थ हो सके। 1990 के दशक में विशेष रूप से देखा गया कि पर्यावरणीय संसाधनों के अतिदोहन तथा अविवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग के कारण पर्यावरणीय ह्रास तथा अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, विकासशील देशों द्वारा ही ऐसे कार्य किये गये। पोषणीयता तथा संघृतता प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्रों का एक अंतःनिर्मित लक्षण है, जो

मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम स्तर पर स्वीकार करता है। यह किसी तंत्र की क्षमता तथा उसके सतत् प्रवाह को अनुरक्षित रखने के लिए सम्बद्ध करता है। पर्यावरणीय तंत्रों में हस्तक्षेप के कारण यह अंतःनिर्मित क्षमता विकृत हो जाती है। इसके विपरीत अर्थशास्त्रियों का मत था कि संसाधनों के दोहन तथा उनके संभावित स्थलों की खोज तथा विकास से ही किसी देश का विकास होता है। विकास तो हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। किसी भी विकास के लिए हमें प्रकृति की सीमा में रहकर ही कार्य करना चाहिए। पर्यावरण से समझौता करके किसी भी प्रकार का विकास नहीं किया जाना चाहिए। पर्यावरण विदों ने पोषणीयता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संरक्षण रणनीति में 1980 में किया गया; लेकिन यह विस्तार 1987 में विशेष रूप से किया गया। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग World Commission on Environment and Development 'WCED' द्वारा उसे सर्वप्रथम प्रचारित-प्रसारित किया गया। WCED के प्रतिवेदन 'Our Common Future' जिसे इसके प्रमुख ग्रीनरलेम ब्रुन्टलैण्ड के नाम के आधार पर ब्रुन्टलैण्ड प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम इस अवधारणा को व्यवस्थित रूप से परिभाषित किया।

इनकी परिभाषा के अनुसार, भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में ह्रास किये बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही संघृत विकास है। संघृतता या पोषणीयता की एकल परिभाषा में विभिन्न विषयों से विचारों को लेकर इसे समग्र रूप दिया गया। अर्थशास्त्र विषय में इसे 'धीमा विकास' या विकास नहीं "Stow growth or No growth" समाजशास्त्र में प्रविधि की समालोचना Critique of Technology' पर्यावरण में संविकास (Ecodevelopment) आदि विचार इसमें रखे गये। आस्ट्रेलिया में इसके लिए 'पारिस्थितिकीय पोषणीय' विकास शब्द द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। संघृत विकास उद्देश्यों पर आधारित होता है, उनमें प्रमुख रूप से मानव की जीवन गुणवत्ता को प्रयुक्त किया जाता है। 'संघृत' विकास उद्देश्यों पर आधारित होता है, उनमें प्रमुख रूप से मानव की जीवन गुणवत्ता सुधार, सामुदायिक

जीवन की देखभाल एवं सम्मान करने, पृथ्वी की धारणीय क्षमता एवं विविधता का संरक्षण, अनव्यकरणीय संसाधनों की गुणवत्ता हास, पृथ्वी की निर्वहन क्षमता को बनाये रखना, व्यक्तिगत दृष्टिकोणों एवं नियमों में परिवर्तन, सक्षम समुदायों अपने पर्यावरण की निगरानी करना, समग्र विकास एवं संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आधार तैयार करना, वैश्विक गठबंधन का निर्माण करना आदि महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 'संघृत विकास' पर्यावरण के ऐसे सकारात्मक संरक्षण पर बल देता है, जिसमें पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों के रक्षण तथा अनुरक्षण, पुनर्स्थापन, दीर्घकालिक दोहन एवं अभिवृद्धि को महत्व दिया गया है। 'संघृत' या 'धारणीय' विकास को संबल प्रदान करने के क्षेत्र में निम्न उपाय प्रभावी हो सकते हैं—

1. संपूर्ण संसाधनों का उपयोग एवं विदोहन उसकी स्थिति एवं उपलब्धता के आधार पर किया जाना चाहिए, यदि नवीकरणीय अथवा अनवीकरणीय संसाधन है तो उसका उपयोग स्वविवेक तथा संघृत विकास के रूप में करना चाहिए।
2. संसाधनों के उपयोग के प्रतिरूपों की अंतर्पीढ़ीय उलझन में इस तथ्य पर बल दिया जाता है कि पर्यावरणीय धरोहर को संरक्षित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बारे में जितनी प्रभावकारी निर्णयन प्रक्रिया अपनाई जाये ताकि भावी पीढ़ियों को लाभ प्राप्त हो सके।
3. समाप्तप्राय संसाधनों के दीर्घकालीन प्रयोग के लिए उनके प्रयोग की तकनीकी तथा विकल्पों के उपाय खोजे जाने चाहिए।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सतत् विकास पर्यावरण हास को न्यूनतम हानि पहुँचाने वाली प्रौद्योगिकी के विकास, जनसंख्या नियंत्रण, संसाधन संरक्षण, भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधन उपयोग की रणनीति बनाने आदि पर

निर्भर है, यद्यपि यह पारिस्थितिकी तंत्र के उपयोग की कोई निरपेक्ष सीमा स्वीकार नहीं करता वरन् इसमें उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास द्वारा संसाधनों की अभिवृद्धि कर आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल देता है। यह कभी भी न समाप्त होने वाला विकास है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो०सिंह, जगदीश : 'बीसवीं सदी में भूगोल के स्वरूप', भौगोलिक चिन्तन के मूलाधार, ज्ञानोदय प्रकाशन, गोरखपुर, 2007, पृष्ठ 429-430
2. 'संघृत विकास', भूगोल और आप, अंक-8, संख्या-5, सितम्बर, अक्टूबर 2009, पृष्ठ 47-48.
3. Brudantland H.D. : 'Our Common Future' (WCED), 1987
4. Mesarovic M.E.E. Pestel, Mankind at the turning point, New York, 1974.
5. Sen, A. The Argumentative Indian Penguin, London, 2005.
6. Stiglitz, J. Toward a New Paradigm of Development : Strategies, Policies and Processes, Special Article, Human Development, Report UNDD-2004.
4. प्रो० सिंह, जगदीश : वहनीय विकास के सामाजिक संदर्भ, 'संविकास संदेश' Journal of Ecodevelopment, Institute for Rural Ecodevelopment, Gorakhpur अंक 15, संख्या-1, जनवरी-2007, पृष्ठ 1-8.
5. प्रो०सिंह, के०एन० 'समन्वित क्षेत्रीय विकास एवं भूगोल' 'संविकास संदेश' Journal of Eco Development, Institute for Rural Eco-Development, Gorakhpur. Vol 17, No. 2, June-2009, pp. 9-18

